नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 345
दि. 18.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

लोकसभा में पास नहीं हुआ 131वां संशोधन बिल, पक्ष में सिर्फ 298 वोट, समझिए नंबर गेम

(जीएनएस)।

लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े परिसीमन संशोधनों पर जारी बहस के बीच शुक्रवार (17 अप्रैल) को बड़ा राजनीतिक मोड़ देखने को मिला। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पर हुई वोटिंग में सरकार को झटका लगा और बिल पास नहीं हो सका। कुल 543 सांसदों वाली लोकसभा में वोटिंग के दौरान 489 सांसद मौजूद रहे, जिनमें से 298 ने समर्थन किया जबकि 230 ने विरोध में वोट डाला। हालांकि संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 352 था, जिसे सरकार हासिल नहीं कर सकी। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल 54 वोट से गिर गया।

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती। 543 सांसदों में के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत थी। लेकिन अगर आज के सांसदों की संख्या देखें तो 528 सांसदों ने ही वोट किया था। 528 सांसदों का दो तिहाई बहुमत 352 है। जबकि पक्ष में सिर्फ 298 सांसदों ने वोट किया है। लोकसभा 18 अप्रैल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।

कौन से तीन बिल पर संविधान में चर्चा?

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश तीन प्रमुख बिल- संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन

विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक-संसद की की बात शामिल है।

सरकार ने इन बदलावों को संरचना और चुनावी नक्शे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं। इनमें लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने और उसी प्रक्रिया के जरिए महिला आरक्षण लागू करने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम बताया, लेकिन विपक्ष ने इसके पीछे राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों का कहना है कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना एक "बैकडोर रणनीति" हो सकती है। उनका आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए चुनावी सीमाओं को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि संसद में महिला आरक्षण के साथ-साथ परिसीमन का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बनकर उभरा है।

"शर्मनाक कानून" क्यों बोले राहुल गांधी? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर तीखा हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें कमजोर करेगा। राहुल ने इसे "शर्मनाक कानून" बताते हुए कहा कि सरकार को पुराना बिल लाना चाहिए, जिसे विपक्ष पूरा समर्थन देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल असल में महिलाओं के हित के लिए नहीं, बल्कि देश के निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे को बदलने की रणनीति का हिस्सा है।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में सामाजिक न्याय का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि यह बिल ओबीसी और दलित समुदायों के लिए "क्रूर" साबित हो सकता है। उनका आरोप था कि सरकार इस कानून के जरिए ओबीसी वर्ग के अधिकारों को कमजोर करना चाहती है। राहुल ने कहा कि देश में इन वर्गों और महिलाओं के साथ क्या होता है, यह सबको पता है, लेकिन सरकार उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है।

बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना "ऑपरेशन सिंदूर-नोटबंदी का जादूगर" वाला बयान दिया, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हो गया। एनडीए सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि राहुल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। स्थिति को संभालने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया और राहुल के विवादित शब्दों को कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया।

महिला आरक्षण बिल पर जारी बहस अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे साफ है कि इस बिल पर सहमति बनना आसान नहीं होगा।

49 दिन बाद खुल गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान ने किया ऐलान

(जीएनएस)।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघरची ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब युद्धविराम की बची हुई अवधि तक "पूरी तरह खुला" रहेगा। इसका मतलब है कि दुनिया भर के सभी कमर्शियल जहाज बिना किसी रुकावट के इस अहम समुद्री रास्ते से गुजर सकेंगे। अराघची ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए साझा की।

कैसे बनी बात?

अराघची ने अपने पोस्ट में साफ लिखा कि यह फैसला लेबनान में चल रहे युद्धविराम के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने कहा, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग को युद्धविराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है।" साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जहाज उसी तय मार्ग से गुजरेंगे, जिसकी घोषणा पहले ही ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन द्वारा की जा चुकी है।

यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से रोजाना वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और ग्लोबल ट्रेड पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए इसका खुला रहना सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है।

पिछले 2-3 हफ्तों में क्या रहा हाल?

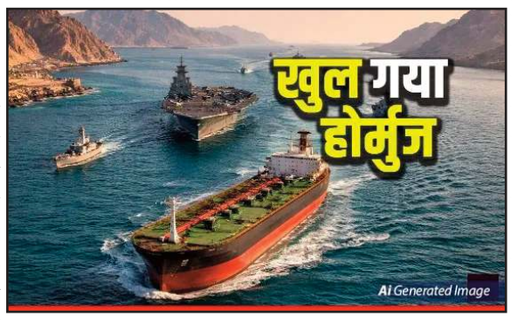

पिछले 2-3 हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि US Central Command की तरफ से क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां तेज कर दी गई थीं। वहीं, ईरान ने भी कुछ जहाजों को रोकने और जांच करने की कार्रवाई की थी, जिससे व्यापारिक जहाजों में डर का माहौल बन गया था। कुछ मामलों में जहाजों को वापस लौटने के लिए भी मजबूर होना पड़ा।

हाल ही में हुए युद्धविराम के बाद दोनों पक्षों ने तनाव कम करने के संकेत दिए हैं। ईरान का यह फैसला उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान फिलहाल टकराव की जगह स्थिरता और आर्थिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कदम से वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

ग्लोबल ट्रेड और भारत के लिए क्या मतलब?

होर्मुज जलडमरूमध्य के खुले रहने से भारत जैसे देशों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि भारत अपनी बड़ी मात्रा में तेल की जरूरत इसी रास्ते से पूरी करता है। अगर यह रास्ता खुला रहता है, तो सप्लाई चेन सुचारू रहेगी और तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का खतरा कम हो जाएगा। कुल मिलाकर, ईरान का यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 99वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के जननायक स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 99वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया और दिवंगत नेता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह एक दूरदर्शी नेता, निडर सांसद और लोकतांत्रिक मूल्यों के अडिग समर्थक थे।

योगी सरकार 1008 श्रद्धालुओं को कराएगी सोमनाथ यात्रा, लखनऊ से 19 अप्रैल को जाएगी विशेष एसी ट्रेन

(जीएनएस)।

लखनऊ : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 19 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से एक विशेष एसी ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना होगी. यात्रा में उत्तर प्रदेश के युवा प्रोफेशनल्स, एमबीए स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एमएसएमई और तकनीकी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं.

समाज के हर वर्ग की भागीदारी भी देखने को मिलेगी. हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदारों से लेकर महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गिग वर्कर्स तक सभी इसमें शामिल हैं. प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए कुल 1008 यात्री इस विशेष यात्रा का

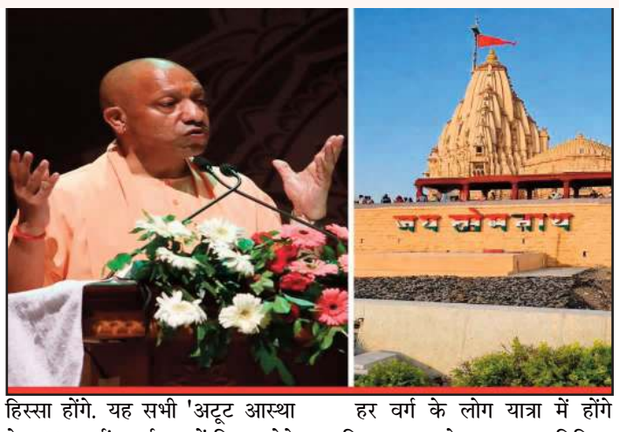

हिस्सा होंगे. यह सभी 'अटूट आस्था के 1000 वर्ष' कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोमनाथ जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को हरी झंडी दिखा सकते हैं.

हर वर्ग के लोग यात्रा में होंगे शामिल : इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, वॉलंटियर्स, युवा प्रतिभाओं, गैर-तकनीकी क्षेत्र के सफल व्यक्तियों, अखाड़ों, शिव मंदिरों और आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को भी इस पहल का हिस्सा बनाया गया है. सीमावर्ती गांवों के निवासी, प्रदेश के कलाकार, पोस्टमैन, रेलवे स्टाफ, सफाई कर्मचारी और ड्राइवर जैसे सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि यह पर्व भारत की आस्था, संस्कृति और आत्मगौरव का प्रतीक है, जिसे जन-जन की सहभागिता के साथ मनाया जा रहा है.

चिंतन शिविर 2026 का समापन किया; आयुष क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य-उन्मुख रोडमैप का हुआ आह्वान

आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय चिंतन शिविर-2026 के समापन सत्र की अध्यक्षता की, जो आयुष क्षेत्र में नीति, शासन और कार्यान्वयन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर के विचार-विमर्श अभ्यास के सफल समापन का प्रतीक है।

लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर था हिंदू रक्षा दल कार्यालय और दिल्ली-6 मॉल, खुलासा

लखनऊ , (जीएनएस)। पाकिस्तान हैंडलर्स के इशारे पर देश में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रचने वाले चार संदिग्ध आतंकियों के मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय और राजनगर एक्सटेंशन के दिल्ली-6 मॉल को विस्फोट व आगजनी के लिए टारगेट बनाया था। दोनों स्थानों की रेकी कर वीडियो और फोटो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे।

एटीएस ने 2 अप्रैल को लखनऊ से मेरठ निवासी साकिब, अरबाब, लोकेश और विकास को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहकर देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहे थे। मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लोकेशन शेयरिंग के साक्ष्य मिले

हैं। जिनसे पता चला कि जब आरोपियों ने इन दोनों स्थानों के वीडियो, फोटो आदि पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे, तब उनकों इसके एवज में 13 हजार रुपये मिले थे। यह रकम विकास द्वारा दिए गए क्यूआर कोड पर ट्रांसफर की गई। सूत्रों के मुताबिक विकास ने अपने जीजा के खाते में यह रकम मंगवाई थी।

अलीगढ़ का कार शोरूम था निशाने पर

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अलीगढ़ के एक कार शोरूम की रेकी की थी, जहां आगजनी की योजना थी। इसके अलावा गाजियाबाद में सड़क किनारे खड़े ट्रकों के वीडियो भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे गए थे। आरोपियों के पास से 24 पर्चे भी बरामद हुए, जिनमें एक तरफ हिंदी व दूसरी तरफ उर्दू में लिखा था कि... हम ऐलान करते हैं कि हम अपने मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपने रास्ते पर चलते रहेंगे।

भारत ने वियना में आयोजित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में समुद्री सुरक्षा नेतृत्व को रेखांकित किया

(जीएनएस)।

भारत ने 14-16 अप्रैल, 2026 को ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में अपनी भागीदारी के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपने सशक्त नेतृत्व का प्रभावी प्रदर्शन किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता भी दोहराई।

अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनाई जा रही सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ये प्रयास एक सुदृढ़, समन्वित और लचीली समुद्री शासन व्यवस्था के निर्माण के प्रति भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं।

वर्ष 2012 में स्थापित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो सीमा प्रबंधन से जुड़ी उभरती चुनौतियों, अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर व्यापक विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करता है। यह मंच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाकर संवाद व सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

अमानक बीज मामले में नुन्हेम्स कंपनी पर एफआईआर दर्ज

(जीएनएस)।

नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने करेला की फसल में अमानक बीज और रोपे से हुए भारी नुकसान का मामला रखा, जिस पर श्री शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह के निदेर्शों के बाद मामले में तेज कार्रवाई हुई और धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी- नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने नई दिल्ली में उनसे भेंट कर करेला फसल में अमानक बीज और रोपे के कारण हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी, जिस पर श्री चौहान ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को साफ कहा कि प्रभावित किसानों को न्याय मिलना

चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस कंपनी की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन निदेर्शों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हुई और मनावर थाना, जिला धार में एफआईआर क्रमांक 266 दर्ज की गई। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 318(4) और 324(5), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराएं 3 व 7 तथा बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिकी में नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।

किसानों की शिकायत है कि उन्होंने नवंबर 2025 में विभिन्न नर्सरियों और कृषि सेवा केंद्रों से संबंधित इस कंपनी के बीज और रोपे खरीदे थे, लेकिन बुआई और रोपण के बाद करेला फसल में अपेक्षित उत्पादन नहीं हुआ और फल छोटे, पीले होकर गिरने लगे। फसल उत्पादन में आई भारी गिरावट के बाद किसानों ने 17 फरवरी 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अमानक बीज एवं अमानक बीज से तैयार रोपे किसानों को प्रमाणित बताकर बेचे गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा। किसानों ने जब दिल्ली आकर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह को ये सब बातें बताई तो श्री चौहान ने कहा कि यह मामला केवल फसल खराब होने का नहीं, बल्कि किसानों के भरोसे, मेहनत और पूंजी को नुकसान पहुंचाने का है।

प्रदेश में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी, राजधानी लखनऊ का पारा 45 डिग्री के पार

लखनऊ । बुंदेलखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को भीषण गर्मी पड़ी। बांदा में तापमान 45.4 डिग्री पहुंचकर सबसे गर्म जिला रहा। प्रयागराज, झांसी और हमीरपुर भी तपिश से बेहाल रहे। मौसम विभाग ने अगले दो दिन गर्मी बढ़ने और बाद में हल्के बादल छाने की संभावना जताई।

उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में शुक्रवार को झुलसाने वाली गर्मी पड़ी। बांदा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। पूर्वा हवाओं की वजह तपिश के साथ उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। बुंदेलखंड के बांदा, झांसी और हमीरपुर जैसे जिलों में दोपहर में जैसे आग बरसी। हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलों में बादलों की आवाजाही भी दिखी। शुक्रवार को बांदा 44.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। वहीं 44 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज दूसरे नंबर पर रहा। 25.2 डिग्री के साथ हमीरपुर में सबसे गर्म रात दर्ज हुई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो दिनों तक फिलहाल गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

यूपी के लिए 29 अप्रैल ऐतिहासिक दिन, दो बड़े कानपुर-लखनऊ व गंगा एक्सप्रेस-वे का होगा लोकार्पण, पीएम मोदी आएंगे

उन्नाव। (जीएनएस)। जनपद में 105 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं अब इस एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। गंगा एक्सप्रेस-वे के साथ ही नवनिर्मित कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के भी लोकार्पण की संभावना जताई जा रही है।

दोनों ही एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संभावित लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जनपद से भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाए जाने के लिए चार्ट बन चुका है। गंगा एक्सप्रेस-वे के असिस्टेंट जनरल मैनेजर पुष्पद के अनुसार फिलहाल कोई लिखित सूचना नहीं आई है। मौखिक के आधार पर हमलोग 29 अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेस वे जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, नेशनल हाइवे कानपुर-लखनऊ व कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे जंक्शन के माध्यम से लिंक है। जिससे संबंधित मार्गों का यातायात गंगा एक्सप्रेस वे पर और गंगा एक्सप्रेस वे का यातायात इन मार्गों पर तय स्थानों से चढ़ उतर सकता है इससे तीनों मार्गों के लगभग एक लाख वाहनों को सुविधा होगी।

राह होगी आसान

गंगा एक्सप्रेस-वे जिले के रास्ते होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ होकर प्रयागराज जा रहा है। इसका निर्माण मेरठ से शुरू हुआ जो विभिन्न जिलों से होते हुए हरदोई तक और फिर हरदोई से बांगरमऊ, सफीपुर, हसनगंज, सदर, पुरवा और बीघापुर तहसीलों के गांव से होते हुए सीधे रायबरेली जिले को जा रहा है।

यहां से लिंक है एक्सप्रेस वे, यातायात को होगी सहूलियत

गंगा एक्सप्रेस-वे की मेरठ से प्रयागराज के बीच कुल लंबाई 594 किमी की है। एक्सप्रेस-वे जनपद में सबसे लंबा 104.8 किमी का है। जिले से ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और कानपुर-लखनऊ राजमार्ग भी निकला है। वहीं, एलीवेटेड कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे अलग रूट से निकल रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे तीनों को क्रास करेगा।

इन मार्गों पर उतर या चढ़ सकते

हरदोई और उन्नाव की सीमा के बीच में आगरा एक्सप्रेस-वे पर जंक्शन वहीं पर बन चुका है। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर सोनिक के पास जंक्शन बनकर तैयार हो चुका है। वहीं नवनिर्मित एलीवेटेड कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर नेवरना में एक जंक्शन बना है। इन जंक्शन से गंगा एक्सप्रेस-वे के वाहन अथवा इन मार्गों का यातायात संबंधित मार्गों पर चढ़-उतर सकेंगे। बांगरमऊ के टिकरिया के पास अंडरपास बन चुका है।

एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित किया जा रहा 248 हेक्टेयर का औद्योगिक गलियारा

जनपद में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे सदर तहसील के बिछिया ब्लाक क्षेत्र के गांव सराय कटियान में दो फेस में जिसमें पहला 132 तो दूसरा 116 कुल 248 हेक्टेयर के अंतर्गत तैयार किया गया औद्योगिक गलियारा भी विकास से संतृप्त किया जा रहा है। जहां अब तक दो विदेशी कंपनियों ने अपने उद्यम लगाए जाने की शुरूआत कर दी है। वहीं अन्य पांच कंपनियां प्रक्रिया के तहत लाइन में है।

गंगा एक्सप्रेस-वे : तहसीलवार गांवों की संख्या

तहसील	गांवों की संख्या
पुरवा	4
बांगरमऊ	11
बीघापुर (पाटन)	19
हसनगंज	7
सदर	15
सफीपुर	20

एक्सप्रेस-वे की खास बातें

कुल 1314.970 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया

उन्नाव क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 625 करोड़ रुपये

छह लेन का गंगा एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है

एक्सप्रेस-वे की ऊंचाई लगभग 8 से 10 मीटर रखी गई है

दोनों ओर 130 मीटर चौड़ाई तक भूमि अधिग्रहण किया गया

करीब 70 से 80 हजार किसानों की भूमि अधिगृहीत हुई

गंगा एक्सप्रेस वे व कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे दोनों के प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण की संभावना बनी है। इसके लिए जिले से भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।

– गौरांग राठी-डीएम

45 मिनट में पूरा होगा लखनऊ से कानपुर का सफर, कितना देना होगा टोल?

(जीएनएस)।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए जल्दी ही शुरू होने वाला है. जिसके बाद दोनों शहरों के बीच सफर बहुत तेज होकर करीब 35-45 मिनट का रह जाएगा. जानिए कितना लगेगा टोल? हाल ही में अभी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है और अब लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाने वाला है. इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसके शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर और भी तेज हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे लगभग 3700 करोड़ रुपये की लगात से बना है और यह 63 किलोमीटल लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे लखनऊ के अमौसी से कानपुर के आजाद चौक तक कनेक्ट करेगा. इस एक्सप्रेसवे की मदद से अब सफर का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा.

कितना होगा टोल रेट?

NHAI के इस एक्सप्रेसवे के लिए अलग-अलग गाड़ियों के टोल रेट तय किए गए हैं जैसे...

अगर बात करें कार, जीप और रवश – एक तरफ का 275 रुपये और वापसी (24 घंटे) 415 रुपये.

हल्के कमर्शियल गाड़ियां – एक तरफ का 445 रुपये और वापसी 670 रुपये.

बस और ट्रक – एक तरफ का 935 रुपये और वापसी 1405 रुपये.

भारी वहन(लउट) – एक तरफ का 1020 रुपये और वापसी का 1530 रुपये.

किन वाहनों को नहीं होगी अनुमति?

बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ चार पहिया और भारी गाड़ियां ही चलेंगी. वहीं दो पहिया, तीन पहिया और छोटी गाड़ियों को अनुमति नहीं होगी, ताकि हाई-स्पीड ट्रैफिक सुरक्षित बना रहें.

कितनी देर में पूरा होगा सफर?

फिलहाल लखनऊ से कानपुर का सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता है, लेकिन नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी सिर्फ 35 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी. इससे लोगों का काफी समय बचने वाला है. यह एक्सप्रेसवे लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है.

जरूरी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे की अधिकतम स्पीड 120 kmph तय की गई है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. अब बहुत ही जल्द लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने वाला है.

लखनऊ अग्निकांड: बची हुई राख में जिन्दगी तलाश रहे मजदूर

पीड़ितों का आरोप है कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर करीब एक घंटे की देरी से पहुंचीं. तब तक आग की लपटें इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि 22 दमकल गाड़ियों को भी काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

(जीएनएस)।

लखनऊ के विकासनगर, सेक्टर-12 के पास बसी एक मजदूर बस्ती बुधवार की शाम मलबे और धुएं के ढेर में तब्दील हो गई. एक झोपड़ी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें 500 से अधिक परिवारों का आशियाना और उनकी जीवन भर की पूंजी खाक हो गई. आरोप है कि दमकल की गाड़ियां सूचना के एक घंटे बाद पहुंचीं. वहीं, झोपड़ियों में रखे सिलेंडरों के धमाकों ने पूरे इलाके को दहला दिया.

स्थानीय निवासियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और प्लास्टिक-तिरपाल से बनी झोपड़ियों के कारण आग ने मिनटों में पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया. बस्ती में रहने वाले पीड़ितों का सबसे बड़ा गुस्सा प्रशासन और दमकल विभाग पर है. पीड़ितों का आरोप है कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर करीब दो घंटे की देरी से पहुंचीं. तब तक आग की लपटें इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि 22 दमकल गाड़ियों को भी काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झोपड़ियों के अंदर रखे घरेलू गैस सिलेंडर एक के बाद एक बम की तरह फटने लगे. स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब 100 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ. इस भगदड़ में लोग अपनी जान बचाकर तो भाग निकले, लेकिन खूंटे से बंधे मवेशी आग का शिकार हो गए. मजदूरों का कहना है कि 50 से 60 मवेशी आग शिकार हुए हैं इसके अलावा कई बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है. हालांकि, प्रशासन ने अभी इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. केवल दो बच्चियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है.

न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा. बिहार के रहने वाले अनिल कुमार इस बस्ती में 30 साल से रह रहे थे. जमीन खरीदने के लिए उन्होंने साढ़े तीन लाख रूपए जमा करके रखे थे जो इस आग की चपेट में आ गए. अनिल आरोप लगते हुए कहते हैं, "यह आग लगाई गई है, लगी नहीं है."

यह आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है. लखनऊ के डीएम विशाख जी. अय्यर ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मामले की जांच मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सौंप दी है. लेकिन यह सवाल अब भी बरकरार है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे जमीन खाली कराने जैसी कोई बड़ी साजिश?

गैस एजेंसी से गायब हो गए 661 सिलिंडर, जांच टीम भी रह गई सन्न

लखनऊ की विहान इंडेन गैस एजेंसी में पूर्ति निरीक्षक की छापेमारी के दौरान स्टॉक से 661 एलपीजी सिलिंडर कम पाए गए। .

विहान इंडेन गैस एजेंसी से 661 सिलिंडर गायब मिले।

प्रोप्राइटर राहुल गंगवार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस।

पहले भी स्टॉक में कमी और रिकॉर्ड में हेरफेर पाया गया।

लखनऊ। (जीएनएस)। अलीगंज की शेखुपुरा स्थित विहान इंडेन गैस एजेंसी में पूर्ति निरीक्षक आरएन मिश्रा की छापेमारी में स्टाक से 661 सिलिंडर कम मिले। पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में एजेंसी के प्रोप्राइटर राहुल गंगवार के खिलाफ विकास नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि 14 अप्रैल को आयल कम्पनी और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने एजेंसी पर छापा मारा। टीम ने स्टाक मिलान किया तो बड़ा हेरफेर सामने आया। स्टाक के मुताबिक 291 खाली और 384 भरे सिलिंडर एजेंसी के नाम पर दर्ज थे लेकिन मौके पर महज 22 खाली सिलिंडर मिले।

एक भी भरा सिलिंडर नहीं था। एजेंसी के प्रोपराइटर पूछने पर संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। जांच में यह भी पता चला कि छह और सात अप्रैल को एजेंसी में मिले 702 सिलिंडर का रिकार्ड रजिस्टर में नहीं दर्ज था।

पूर्व में 23 मार्च को भी जांच की गई थी जिसमें 318 सिलिंडर कम मिले थे। एजेंसी संचालक को नोटिस दिया गया था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल विकास नगर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

नेत्र चिकित्सक भर्ती: लखनऊ हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्रों पर लगाई अंतरिम रोक

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नियमित नेत्र चिकित्सकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न जारी किए जाएं।

नियमों में संविदा कर्मियों को वरीयता

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि देने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। साथ ही राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो मामले में उचित आदेश पारित किया जाएगा।

'कानून रक्षा के लिए, न कि...', थारू जनजाति के वन अधिकारों पर लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

(जीएनएस)।

लखनऊ हाईकोर्ट ने थारू जनजाति के वन अधिकारों के खिलाफ आए लखीमपुर खीरी जिला समिति के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि जब तक नया आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक याची अपने मौजूदा वन अधिकारों का उपयोग पहले की तरह करते रहेंगे. मामले के याची लखीमपुर खीरी के पलिया कला के थारू जनजाति से संबंधित हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है.

यूपी में थारू जनजाति के वन अधिकारों से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट है. लखनऊ हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी जिला समिति का आदेश रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है, तब तक वनवासियों के अधिकार बहाल रहेगा. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के वन अधिकार मामले में जिला स्तरीय समिति के आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचियों के दावों पर सुनवाई कर समयबद्ध ढंग से नया आदेश पारित किया जाए. जब तक नया आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक याची अपने मौजूदा वन अधिकारों का उपयोग पहले की तरह करते रहेंगे.

5 साल पहले पहुंचे हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने ह्रुउदासा व अन्य बनाम भारत संघह्व की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. मामले के याची लखीमपुर खीरी के पलिया कला के थारू जनजाति से संबंधित हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है. याचियों ने 15 मार्च 2021 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके सामुदायिक वन अधिकारों के दावों को खारिज कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने कहा कि जिला स्तरीय समिति ने वन अधिकार अधिनियम 2006 की मंशा और प्रावधानों पर समुचित विचार नहीं किया. केवल वर्ष 2000 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर फैसला दे दिया.

उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और उनकी आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसे वनवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना कानून का मूल उद्देश्य है. अदालत ने कहा कि याचियों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए और सभी तथ्यों, अभिलेख पर विचार करते हुए कारण युक्त आदेश पारित किया जाए.

लखनऊ में 500 वाहनों को खड़ा करने के लिए बनेगी हाईटेक पार्किंग, जगह भी हो गई फाइनल

(जीएनएस)।

लखनऊ। गोमती नगर के विवेक खंड दो में भूमिगत पार्किंग बनाने के लिए गोमती नगर जनकल्याण महासमिति ने प्रयास तेज कर दिए हैं। विवेक खंड दो में बनने वाली यह ऐसी भूमिगत पार्किंग होगी जो आधुनिक सुविधाओं से जहां लैस होगी, वहीं गोमती नगर के विवेक खंड दो व आसपास क्षेत्र का जाम पूरी तरह नियंत्रित करने में सहायक भी होगी। इसमें स्मार्ट व्हीकल गाइडेंस एंड नेविगेशन होगा।

आधुनिक सिक्योरिटी और सर्विलांस की सुविधा भी। आटोमेटेड पार्किंग के साथ ही वैलेट सिस्टम भी होगा। एसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रानिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा सहित अन्य सुविधाओं से यह परिसर लैस होगा।

खासबात है कि विवेक खंड दो स्थित लक्ष्मण मण्डपम के सामने स्थित पार्क में यह पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। महासमिति के महासचिव डा. राघवेंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रस्ताव बनकर तैयार है, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसे बनाना है। जल्द ही लोकार्पण इसका होना है।

इस प्रयास से पत्रकारपुरम से लेकर विवेक खंड दो, तीन, रेलवे स्टेशन, मिठाई वाला चौराहे के आसपास के व्यापारी व ग्राहक अपने चार पहिया वाहन खड़ा कर सकेंगे। भूमिगत पार्किंग में चार पहिया वाहन 410 खड़े हों सकेंगे और दो पहिया वाहन 84 खड़े हो जाएंगे। पार्किंग का कुल क्षेत्र 14,176 वर्ग फिट का होगा। यह अपर ग्राउंड व लोअर ग्राउंड में बनाई जाएगी।

महासिमित के अध्यक्ष प्रो (डा.) बीएन सिंह और सचिव संजय निगम कहते हैं कि गोमती नगर में सरकारी महिला डिग्री कालेज का स्थान तो है लेकिन डिग्री कालेज खुलवाने का प्रयास जारी है। महिला डिग्री कालेज में ही ला कालेज की स्थापना भी की जाएगी। उद्देश्य होगा कि छात्राओं को एक छत के नीचे उच्च शिक्षा मिल सके।

इसके अलावा गोमती नगर में रेलवे स्टेशन तो खुल गया है, इससे गोमती नगर, इंदिरा नगर, चिनहट, शहीद पथ सहित चार लाख से अधिक आबादी को लाभ मिल रहा है। भविष्य में मुंशी पुलिया तक जाने वाली मेट्रो को विस्तार देते हुए गोमती नगर से भी जोड़ने की जरूरत है।

निगम कहते हैं कि अगर यह सुविधा मिल जाए तो गोमती नगर भी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के साथ ही नए व पुराने लखनऊ से मेट्रो के जरिए गोमती नगर से जुड़ा जाएगा। लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी में केंद्र व प्रदेश सरकार कर रही है। पुराने लखनऊ में मेट्रो का विस्तार इसी की बानगी है।

समिति सदस्य कर्नल एएन पांडे व पीआर पांडे ने बताया कि विक्रांत खंड में जर्जर सड़कों एवं नालों के फिर से निर्माण को लेकर आवाज उठाई जा चुकी है। उम्मीद है कि कार्यदायी संस्थाएं जल्द ही इस दिशा में काम करेंगी।

महासमिति सदस्य केके मौर्य और सी गोपाल कृष्णन नायर ने बताया कि विनीत खंड पांच और छह में पुरानी सीवर पाइपलाइन को बदलना और विकास खंड पांच में जिम जैसे कार्य भी महासमिति की सूची में प्राथमिकता है। इन पर जल्द ही काम होगा।

लखनऊ में नकली सोना गिरवी रखकर बैंक से लिया 7.14 लाख का लोन, जालसाज और वैल्यूवर पर एफआईआर

(जीएनएस)।

लखनऊ। नकली सोना गिरवी रखकर जालसाज ने बैंक आफ इंडिया से 7.14 लाख का लोन करा लिया। लोन से पहले बैंक के वैल्यूवर सराफ ने सोने के जेवर को 22 कैरेट का बताते हुए रिपोर्ट दी।

किस्त जमा न होने पर बैंक ने लोन धारक को नोटिस देने के बाद गिरवी जेवर की नीलामी का प्रक्रिया शुरू की। दूसरे वैल्यूवर ने जेवर की जांच की तो वह नकली मिले।

बैंक के शाखा प्रबंधक ने रहीमाबाद थाने में लोन धारक व वैल्यूवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

चौक के चढ़ाई माहू लाल निवासी अभिजीत शुक्ल बैंक आफ इंडिया गहदो शाखा के प्रबंधक हैं। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी 2023 को माल के करेंद निवासी संतोष कुमार ने 27 फरवरी 2023 को बैंक में गोल्ड लोन के लिए आवेदन किया था।

बैंक द्वारा सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद 7.14 लाख का लोन स्वीकृत कर दिया था। लोन के एवज में संतोष ने 185.038 ग्राम के जेवर व सिक्के गिरवी रखे थे। गिरवी जेवर की शुद्धता की जांच बैंक के अधिकृत वैल्यूवर सत्यम सोनी ने की थी।

आठ दिसंबर को दोबारा नोटिस भेजी गई लेकिन न भुगतान किया और न ही जवाब दिया गया। जिसके बाद बैंक द्वारा गिरवी जेवर को नीलाम करने की सूचना लोन धारक संतोष कुमार को दी। साथ ही बैंक ने गिरवी जेवर का पुनः मूल्यांकन कराया। अधिकृत वैल्यूवर अंकुर सोनी ने अपनी रिपोर्ट दी तो पता चला कि जेवर नकली हैं।

लखनऊ का पुराना नाम क्या था, क्यों कहा जाता है नवाबों का शहर, यूपी की राजधानी का रोचक इतिहास

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पर क्या आप जानते हैं कि पहले इसका नाम कुछ और था। अभी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहां से जुड़ी कई प्रसिद्ध चीजों के बारे में परीक्षाओं और इंटरव्यू में सवाल घूमते दिख जाते हैं, इसलिए यहां इसके बारे में जानें। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की राजधानी लखनऊ का इतिहास इसे और भी खास बनाता है। लखनऊ का पुराना नाम कुछ और था और अभी इसकी पहचान नवाबों के शहर की है। अवध के नवाबों ने यहां कला, संस्कृति और वास्तुकला को नई पहचान दी थी।

समय के साथ लखनऊ यूपी की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी बना। आज यह शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, तहजीब और गंगा-जमुनी संस्कृति के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इसके बारे में जीके के सवाल-जवाब प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहां इसका इतिहास जानें।

लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह शहर अपनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। 'ॡ'ल्लङ्ब्द.ल्लू.ल्ल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लखनऊ का पुराना नाम लखनपुरी था, जिसे भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण के सम्मान में रखा गया था। समय के साथ यह नाम बदलकर वर्तमान लखनऊ के रूप में जाना गया। लखनऊ अपने अदब, खानपान और वास्तुकला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। आज यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है जिसका देश के इतिहास में विशेष स्थान है।

लखनऊ का इतिहास क्या है?

ऐसा माना जाता है कि लखनऊ की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजवंश से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण के सम्मान में इसे पहले लखनपुरी कहा जाता था। शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित लक्ष्मण टीला इस कथा को विश्वसनीयता प्रदान करता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र कोसल के महाजनपद का हिस्सा था और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है।

इसलिए कहा जाता है 'नवाबों का शहर'

लखनऊ को 'नवाबों का शहर' कहा जाता है क्योंकि यहां नवाबी संस्कृति और शाही जीवन शैली बहुत प्रसिद्ध थी। अवध के नवाबों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में लखनऊ को भव्य राजधानी बनाया था। नवाब आसफ-उद-दौला और सादत अली खान के शासनकाल में शहर में कई महल, इमामबाड़े, कर्बला और अन्य स्मारक बनाए गए। यूरोपीय शैली और मुगल वास्तुकला के मिश्रण से लखनऊ को अनोखी शैली के लिए जाना जाता है। बड़े इमामबाड़ा, रूमी गेट और बिबियापुर कोठी जैसी इमारतें इसकी भव्यता का प्रतीक हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

सुरक्षित और निर्बाध समुद्री परिवहन अत्यंत आवश्यक

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता टोक्यो में आयोजित एज़ेडईसी-प्लस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विश्वभर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि समुद्री रास्ते केवल व्यापार के साधन नहीं हैं बल्कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत का यह रुख उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत ने इस मंच पर सुरक्षित और निर्बाध समुद्री परिवहन को अत्यंत आवश्यक बताया। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि हाल के वर्षों में कई समुद्री क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष की स्थितियां बनी हैं, जिनका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा है। व्यापारिक जहाजों पर हमले न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं बल्कि वे वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा हैं। एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हमलों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ कड़े वैश्विक प्रयास जरूरी हैं। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर भी भारत ने विशेष ध्यान आर्कषित किया। आज के समय में ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का आधार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यदि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो इसका प्रभाव उद्योगों, परिवहन और रोजमर्रा के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ता है। इस संदर्भ में भारत ने साझेदारी और सहयोग के जरिए ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और स्थिर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया, जिनमें अनवर इब्राहिम और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शामिल थे। इन नेताओं ने भी ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों पर अपने-अपने विचार साझा किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और ऊर्जा के विविध स्त्रोतों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तरलीवृत प्रावृतिक गैस यानी एलएनजी के उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से मलेशिया क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

मेजर 'शैतान' सिंह और 'छोटू' राम के नाम अब अपमान हो गए! स्कूली पढ़ाई सुधारोगे या सिर्फ बच्चों के नाम बदलोगे?

(जीएनएस)।

राजस्थान शिक्षा विभाग का सार्थक नाम अभियान विवादों में है. विभाग का मानना है कि 'टिंकू, शैतान, कालू' जैसे नामों से बच्चों का आत्मविश्वास गिरता है, इसलिए वह 3000 'सार्थक' नामों की लिस्ट सुझा रहा है. हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सम्मान नाम से नहीं, काम से मिलता है; जैसे परमवीर मेजर शैतान सिंह और सर छोटू राम. सवाल है कि विभाग पढ़ाई और शिक्षकों की स्थिति सुधारने के बजाय नाम बदलने में क्यों उलझा है?

राजस्थान सरकार की पॉलिसी विवादों में है.

नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर का यह मशहूर जुमला आज राजस्थान के गलियारों में नई बहस छेड़ चुका है. एक तरफ वो वीरधरा है जिसने 'शैतान सिंह' जैसे परमवीर पैदा किए तो दूसरी तरफ सरकार का 'सार्थक नाम अभियान' है जो कहता है कि 'शैतान' या 'टिंकू' जैसे नाम बच्चों के आत्मविश्वास को कम कर देते हैं. राजस्थान का शिक्षा विभाग अब स्कूलों में बच्चों के नाम सुधारने की लिस्ट बांट रहा है लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या शिक्षा विभाग का काम नाम बदलना है या स्कूलों की बदहाल शिक्षा को दुरुस्त करना? राजस्थान शिक्षा विभाग का मानना है कि 'बबलू, छोटू, कालू, गोबरी या शैतान' जैसे नाम 'निरर्थक' और 'नकारात्मक' हैं, जिनसे बच्चों का मजाक उड़ता है. इसके बदले विभाग ने 3000 से ज्यादा 'सार्थक' नामों की एक सूची जारी की है, जिसमें 'आरव, अथर्व और आराध्या' जैसे नाम सुझाए गए हैं. सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों में गौरव की अनुभूति होगी.

जारी कर दी नाम की लंबी लिस्ट

यहां शहरों के नाम की बात नहीं हो रही. बच्चों के नाम क्या होने चाहिएं ये बात रही है सरकार. राजस्थान का शिक्षा विभाग कह रहा है कि शेरू, शैतान, कालू, टिंकू, छोटू, बबलू, कचूम्बर, धापा, गोबरी, बावरी जैसे नाम बच्चों के नहीं होने चाहिए. ऐसे नामों की वजह से बच्चे स्कूल में मजाक का शिकार हो जाते हैं और उन्हें शर्मिंदगी होती है. और बड़ा होने पर उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है. कहा गया कि नाम सार्थक होना चाहिए ताकि बच्चा गर्व महसूस करे. वो तो ठीक है लेकिन पब्लिक तो पहले ये देख रही है कि शिक्षा विभाग ये सब भी करता है क्या? सरकार कह रही है जबरदस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ.नाम बदलने के लिए नए नाम सुझाएंगे. जी. नाम सरकार सुझाएगी. सार्थक नामों की लिस्ट बनाई है सरकार ने. लड़कों के 1409 नाम और लड़कियों के 1541 नामों की लिस्ट बनाई है. इनमें कोई नाम चुन लो. आरव रख लो, अथर्व रख लो, अखंड रख लो, बालमुकुंद रख लो, बद्रीनाथ रख लो, आराध्या रख लो, अन्नपूर्णा रख लो, वैष्णवी रख लो.

कह रहे हैं ये सम्मानजनक नाम है. तो क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों का आत्मविश्वास इसलिए कम होता है क्योंकि उनके माता-पिता ने उनका नाम टिंकू रख दिया. बबलू रख दिया? पढ़ाई अच्छी हो जाएगी सरकारी स्कूलों में तो आत्मविश्वास अपने आप नहीं बढ़ जाएगा. जब बच्चा काबिल बन जाएगा और दुनिया में कुछ कर के दिखाएगा किसी क्षेत्र में तो उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ जाएगा. शिक्षा विभाग के अधिकारी पढ़ाई बहतर करवाने के लिए कुछ करें वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? टीचर आ

राजस्थान सरकार की पॉलिसी विवादों में है. (AI Image)

रहे हैं या नहीं आ रहे, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, कॉपी किताब मिल पा रहे हैं, बच्चों को या नहीं मिल पा रहे. ये सब हो गया क्या कि शिक्षा विभाग नामों की लिस्ट बना कर दे रहा है कि बच्चों के नाम ये रखने चाहिएं.

टीचर माता-पिता से बात कर देंगे सुझाव

अगर संस्कार की ही बात है तो वो मां-बाप ही तय करते हैं ना. उनका बच्चा है वो नाम देते हैं और बच्चे को पसंद नहीं अपना नाम तो बड़ा हो कर खुद बदल लेता है. कई लोग अपने नाम हाई स्कूल के सर्टिफि केट का फॉर्म भरने के टाइम बदल भी लेते हैं. क्योंकि फिर ज़िंदगी भर के लिए वो उनका नाम हो जाता है कागजों में. तो वो उनकी मजी ना. सरकार क्यों पड़ रही है इसमें? शिक्षा विभाग अपना काम करे ना. अगर बबलू का नाम आप अथर्व रखवा भी दोगे कागज पर तो बुलाएंगे तो उसको बबलू ही और क्या प्रॉबलम है उसमें? लेकिन कह रहे हैं स्कूल टीचर माता-पिता से बात करेंगे. अगर माता-पिता सहमत हों, तो बच्चे का पुराना नाम स्कूल रजिस्टर में सकता है. और नए एडमिशन वाले बच्चों के माता-पिता को भी ये लिस्ट दिखाई जाएगी, ताकि वो सरकार के हिसाब से जो अच्छा नाम है वो चुन सकें. हालांकि स्कूल किसी का नाम जबरदस्ती नहीं बदलेगा. माता-पिता की सहमति से ही नाम बदला जाएगा. कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं होगा. तो फिर क्यों? क्यों पड़ गया है फिर शिक्षा विभाग इस चक्कर में? और किसने कह दिया नाम से ही सम्मान होता है? सम्मान काम से होता है ना, व्यक्तित्व से होता है.

छोटू राम यूनिवर्सिटी का क्या करेंगे?

राजस्थान के बगल में ही हरियाणा है. कह दो वहा जा कर कि छोटू नाम में कोई सम्मान नहीं. कह के तो देखो. सबसे बड़े विचारक और समाज सुधारक हुए जो ना वहां से, उनका नाम था चौधरी राम रिछपाल ओह्लयान. लेकिन चौधरी राम रिछपाल ओहल्यान यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटू राम यूनिवर्सिटी है. छोटू राम चौक है, छोटू राम पावर स्टेशन है, छोटू राम कॉलेज है, बहुत कुछ है. क्योंकि उनको जानते ही सर छोटू राम के नाम से हैं. उनने मां-बाप को क्या बोलना था आपने? कि छोटू राम नाम ठीक नहीं है? जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन सार्थक बना दिया उनका नाम सार्थक नहीं है? किस टाइप की बहस है ये? क्यों बहस है ये? क्यों करना है ये सब? और हरियाणा छोड़ो, राजस्थान में ही आ जाओ. 1962 की भारत-चीन जंग के दौरान, लद्दाख के चूशुल इलाके में रेजांग ला नाम की जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी. वहां बफीर्ली हवाएं चलती है, भयंकर ठंड होती है (-40) डिग्री तक की और हमारें सैनिकों के पास पुरानी बंदूकें थीं कहानी पता है ना आपको? सेना की चार्ली कंपनी के मजेर सिर्फ 120 जवानों के साथ इस ऊंचे दर्रे की रक्षा कर रहे थे. चूशुल में एयरफील्ड था, वहां तक पहुंचने से चीन की सेना रोकना था. कोई रिजर्व फोर्स नहीं थी, कोई और मदद नहीं मिल सकती थी उनको. सिर्फ. 120 थे. 18 नवंबर 1962 की सुबह, अंधेरे में अचानक हमला शुरू हुआ. 3000 से ज्यादा चीनी सैनिक पहाड़ी खाइयों से चढ़ते हुए आए. भारी तोपों, मोर्टार और मशीन गनों से बारिश जैसी गोलियां बरसने लगीं. मेजर ने हिम्मत नहीं हारी. वो एक पलटन से दूसरी पलटन तक दौड़ते रहे. गोलियों के बीच में, खुली जगह में.

मेजर शैतान सिंह सिंह की वीर गाथा

जवान चिल्लाते रहे, ह्लसर, आप कवर लो!ह्व लेकिन वो कहते रहे, कि ह्लमैं यहां हूं, लड़ो! पीछे नहीं हटेंगे!ह्व पहला हमला रोका और दुश्मन के सैकड़ों सैनिक ढेर कर दिए. फिर दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला हुआ. लेकिन हर एक भारतीय जवान ने 4-5 चीनी सैनिक मारे. ठंड इतनी थी कि हमारे हथियार जाम हो रहे थे, हाथ-पैर सुन्न पड़ गए थे. फिर भी हमारे जवान लड़ते रहे. हम 120, वो 3000. मेजर के पेट में गोली लगी. मेजर के हाथों में गोलियां लगीं. खून बहता जा रहा था. उनके जवान उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन दुश्मन ने मशीन गन चल दी. तब मेजर का आखिरी आदेश था कि ह्लमुझे छोड़ दो, खुद बचो और लड़ते रहो!ह्व सुबह तक लड़ाई चली. जब सब शांत हुआ, तो 114 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे. सिर्फ कुछ बच पाए. लेकिन रेजांग ला बच गया. चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ और उनका आगे बढ़ना रुक गया. पता है जवानों के शरीर कब मिले थे. तीन महीने बाद बर्फ.में जमे हुए, 13 कुमाउं बटैलियन के उन जवानों के शरीर जब मिले तो उनके हाथों में उनकी बंदूकें थीं. शरीर जमा हुआ था. हाथ में बंदूक थी. जैसा उनका मेजर था, वैसे मेजर के जवान थे. मेजर के पार्थिव शरीर के साथ भी उनका हथियार बंधा हुआ मिला था. आखिरी सांस तक लड़े थे मेजर. वीरता की ऐसी मिसाल पेश की थी जोधपुर से आने वाले मेजर ने कि उनको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था. आखिरी सांस तक लड़े, आखिरी गोली तक लड़े. वो भी राजस्थान के ही थे. उनकी वीरता की कहानी बच्चे-बच्चे को सुनानी चाहिए देश के. मेजर शैतान सिंह. शैतान नाम था उनका. मां-बाप ने रखा था. सम्मान नहीं है इस नाम में. राजस्थान के सबसे बड़े सपूत के नाम में सम्मान नहीं है? तो स्कूलों को ठीक कर दो, पढाई ठीक करवा दो, टीचर अच्छे रखवा दो, शिक्षा विभाग का जो काम है वो करो ना. नाम बदलने से नाम नहीं होगा. नाम तो बच्चे खुद कर देंगे राजस्थान का. काम ऐसा हो कि हर गांव से एक शैतान निकले, मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र. सौ बात की एक बात.

'देश के वफादार होंगे लेकिन...'सेना के जवानों पर कमेंट करने वाली इंफ्लूएंसर इशिता पुंडीर पर एफआईआर

हिमाचल प्रदेश की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर इशिता पुंडीर के भारतीय सेना पर दिए गए कथित विवादित बयान से बवाल मच गया है. माफी मांगने के बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी और संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

(जीएनएस)।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. सोलन-नाहन क्षेत्र की रहने वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर इशिता पुंडीर के खिलाफ भारतीय सेना को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई है.

'पत्नी के प्रति वफादारी पर सवाल'

आरोप है कि इशिता ने अपने एक वीडियो में कहा था कि सेना के जवान भले देश के लिए कितने भी वफादार हों लेकिन वह अपनी पत्नियों या

महिलाओं के प्रति वफादार नहीं होते. यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. बड़ी संख्या में लोगों ने इस टिप्पणी को सेना के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मामला बढ़ने के बाद इशिता पुंडीर ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और यदि उनके बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए खेद व्यक्त करती हैं. हालांकि, माफी के बावजूद विवाद थमता नहीं दिखा और शिकायत दर्ज कराई गई.

इशिता पुंडीर पर एफआईआर

यह शिकायत कांग्रेस के यादोपति ठाकुर ने एसपी सिरमौर को दी. अपने पत्र में उन्होंने इशिता के बयान को गंभीर बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदार पोस्ट को लेकर बहस छेड़ दी है.

एक मिलियन हैं इशिता के

बता दें कि इशिता पुंडीर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. उनके इंस्टाग्राम पर एक मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक और यूट्यूब पर भी उनकी बड़ी पहुंच है. ऐसे में उनके बयान का प्रभाव और अधिक व्यापक स्तर पर पड़ा, जिससे विवाद और गहरा गया. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

'एक छोटे लड़के' ने उड़ा दी पूरे भारत की नींद, दुनिया में भी बढ़ी हलचल

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः एक छोटे बच्चे ने इन दिनों भारत समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। उसका यह 'खेल' सबको भारी पड़ने वाला है। 2026 में लोग इस छोटे लड़के की वजह से परेशान रहने वाले हैं। यह छोटा लड़का है 'अल नीनो', जिसे स्पेनिश में 'द लिटिल बॉय' कहा जाता है। इसके बारे में भारतीय मौसम विभाग (क्टऊ) ने भी चिंता जताई है। मौसम विभाग ने 2026 में मानसून के औसत से भी नीचे रहने का अनुमान जताया है। इसके पीछे यही छोटा लड़का यानी अल नीनो ही है, जो इन दिनों प्रशांत महासागर के एक छोटे से हिस्से में विकसित हो रहा है। इस बीच, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया था।

मौसम विभाग ने जताई अल नीनो की चिंता

भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2026 में जून से लेकर सितंबर तक मानसूनी बारिश औसत से भी कम हो सकती है, क्योंकि अल नीनो विकसित हो रहा है। अल नीनो एक ऐसी मौसमी परिघटना है, जिससे दुनिया के दूसरे हिस्से में बारिश कम होती है। सूखा पड़ता है। इससे फसलें खराब हो जाती है। दानें कम पड़ते हैं। कुल मिलाकर अन्न का उत्पादन कम रह सकता है।

क्या है यह अल नीनो, कहां बनता है

अल नीनो को 'द लिटिल बॉय' के साथ-साथ 'क्राइस्ट चाइल्ड' भी कहा जाता है। अल नीनो पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में होने वाली मौसमी परिघटना है, जिससे पर्यावरणीय चक्र गड़बड़ा जाता है और बारिश लाने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती है। इससे मानसूनी सीजन के दौरान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कम बारिश होती है। अल नीनो हर 2 से 7 साल के बीच विकसित होता है।

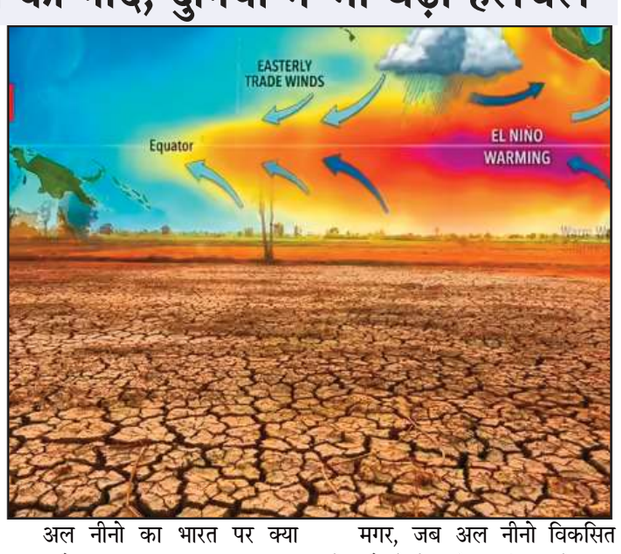

अल नीनो का भारत पर क्या पड़ता है असर

आम तौर पर महासागरों से गर्म हवाएं उठती हैं और अपने साथ पानी को सोखकर किसी दूसरे हिस्से में बारिश करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जुलाई से लेकर सितंबर तक भारी बारिश करती हैं।

मगर, जब अल नीनो विकसित होता है तो ये गर्म हवाएं कमजोर पड़ जाती है और ठंडी हो जाती है, जिससे ये पानी कम उठा पाती हैं। और इसका असर मानसून पर पड़ता है, जो कमजोर पड़ जाता है और बारिश कम होती है।

भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार मंच ने व्यापार और निवेश में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत किया

(जीएनएस)।

भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार मंच का आयोजन नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर, डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर की यात्रा के अवसर पर किया गया। ऑस्ट्रिया के अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री, वोल्फगैंग हाटमैन्सडॉर्फर ने भी इस मंच में भाग लिया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। इस मंच ने वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों, नीति-निमार्ताओं और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाकर व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के अवसरों का अन्वेषण किया।

मंच के दौरान एक द्विपक्षीय फास्ट-ट्रैक तंत्र (एफटीएम) पर हस्ताक्षर किए गए और उसे लागू किया गया। यह तंत्र भारत में ऑस्ट्रियाई कंपनियों और निवेशकों तथा ऑस्ट्रिया में भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है, जिससे निवेश को सुगम बनाया जा सके, समस्याओं का समाधान किया जा सके और उनके समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित किया जा सके। यह दोनों देशों में व्यवसाय करने में सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव साझा करने का भी एक मंच होगा, जो निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्यापार मंच ने भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम चिह्नित किया। यह यात्रा चार दशकों से अधिक समय में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत-यूरोपीय संघ के व्यापक आर्थिक ढांचे में भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। दोनों पक्षों ने वर्तमान स्तर से परे द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने और औद्योगिक क्षमताओं, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर पूरकताओं का लाभ उठाने की मंशा व्यक्त की।

मंच में हुई चचाओं ने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के महत्व को रेखांकित किया, जो व्यापार की विस्तार, बाधाओं को कम करने और निवेश प्रवाह को सुगम बनाने में एक प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। मंच ने स्थायी विकास, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकियों को भविष्य के सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में भी चिह्नित किया। यह एफटीए श्रम-प्रधान क्षेत्रों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बेहतर बाजार पहुंच और सुधारित नियामक ढांचे के माध्यम से नए अवसर उत्पन्न करने की अपेक्षा रखता है।

सरकार और उद्योग से जुड़े हितधारकों ने प्रस्तावित समझौते के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसायों द्वारा सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उद्योग प्रतिनिधियों को इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि एमएसएमई और नवाचार-आधारित उद्यमों सहित व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत व्यापक आर्थिक आधारशिला और वैश्विक चुनौतियों के बीच उसकी लचीलापन क्षमता को उजागर किया। उन्होंने पुनःऔद्योगीकरण तथा उन्नत विनिर्माण और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने जैसे सुधारों की भूमिका को विकास के प्रमुख चालक के रूप में बताया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अवसरों की खोज करने और दीर्घकालिक संवाद के लिए व्यापार मंच को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर, महामहिम डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में एक उपलब्धि बताया और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में निरंतर वृद्धि को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि व्यापार लगभग 3 अरब यूरो तक पहुँच चुका है और लगभग 160 ऑस्ट्रियाई कंपनियाँ भारत में कार्यरत हैं। उन्होंने भारत की विकास यात्रा और एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उसके महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की क्षमता वाले भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की संभावनाओं को भी उजागर किया।

भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार मंच ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव और भविष्य की संभावनाओं की पुनः पुष्टि की। समान प्राथमिकताओं, परस्पर पूरक ताकतों और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ, दोनों देश अपनी आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

कोयला मंत्रालय ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास तेज किए

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय ने आज 'आत्मनिर्भर भारतः ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला' विषय पर हितधारकों के परामर्श सत्र का आयोजन किया। इसके साथ ही वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 15वें दौर का भी शुभारंभ किया गया। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पूरे दिन चले इस परामर्श सत्र में नीति निमार्ताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने हिस्सा लिया, जिसमें सुधारों, तकनीकी प्रगति, कोयला गैसीकरण, स्थिरता और समावेशी विकास पर चर्चा की गई, जो भारत के कोयला क्षेत्र के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिरिक्त सचिव एवं नामित प्राधिकरण सुश्री रूपिंदर बरार, कोयला नियंत्रक श्री सजीश कुमार एन, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा कोयला क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारक भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री

विक्रम देव दत्त ने वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वें दौर की नीलामी का शुभारंभ किया। 15वें चरण में कुल 11 कोयला ब्लॉक पेश किए जा रहे हैं, जिनमें 7 पूर्ण रूप से अन्वेषित और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। इनमें से 3 खदानें कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी) के तहत और 8 खदानें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) के तहत पेश की जा रही हैं। इसमें 1 कोकिंग कोयला ब्लॉक शामिल है, जबकि शेष 10 गैर-कोकिंग कोयला ब्लॉक हैं, जो इस्पात और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त, 13वें चरण के दूसरे प्रयास के तहत 6 कोयला खदानें भी पेश की जा रही हैं।

नीलामी के लिए प्रस्तुत खदानें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कोयला/लिग्नाइट समृद्ध राज्यों में स्थित हैं, जिनसे बड़े निवेश आकर्षित होने, घरेलू कोयला उपलब्धता बढ़ने और रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

अब तक, कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदानों की 13 चरणों की नीलामी के माध्यम से सफलतापूर्वक 135 कोयला खदानों की नीलामी की है, जिनकी कुल 'पीक रेटेड कैपेसिटी' (पीआरसी) लगभग 325 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। यह भारत की कोयला क्षमता को उजागर करने की दिशा में मजबूत गति को दर्शाता है।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि कोयला क्षेत्र में किए गए संरचनात्मक सुधार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिनमें पारदर्शिता, दक्षता और क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को उभारने पर निरंतर ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था की शुरूआत इस क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी कदम साबित हुई, जिसने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने और घरेलू उद्योगों के लिए कोयले की उपलब्धता में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। अब तक हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं, जिनमें अधिक संख्या में खदानों की नीलामी, निवेशकों की बढ़ती रुचि और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं का सुदृढ़ होना शामिल है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि नीलामी के हर अगले चरण में भागीदारी लगातार बढ़ी है, जो हितधारकों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, उन्होंने प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के बीच समन्वित और सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला।

लड़के को तंदूर में फेंकने का मामला; बस्ती में दो आरोपी गिरफ्तार, लखनऊ में चल रहा इलाज

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि दो आरोपियों को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार किया गया है.

बस्ती : जनपद के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलौली गोसाई गांव में 11 वर्षीय बालक को तंदूर में फेंके जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने शुक्रवार को दो नामजद आरोपियों को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ था.

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि मलौली गोसाई निवासी देवी प्रसाद निषाद ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका बेटा चमन उर्फ अमर निषाद (11) एक शादी कार्यक्रम में गया था. इस दौरान बालक तंदूर की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया था. आनन-फानन में घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने दी जानकारी. उन्होंने बताया कि मामले

की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था. शुक्रवार को सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर घटना के वांछित अभियुक्तों लाल जी निषाद (35) और रमेश निषाद (27) को जमौलिया कट के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान जो भी नए तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

यह था मामला : बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलौली गोसाई गांव में एक विवाह समारोह के दौरान एक रसगुल्ले को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि एक रसगुल्ले को लेकर कैटरिंग ठेकेदार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं थीं. उसने एक बालक (11) को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया था. आरोप है कि आग की लपटों से बच्चा चेहरे से लेकर कमर तक बुरी तरह झुलस गया था. उसे गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है.

लखनऊः बोर्ड परीक्षा में कम नंबर और मोबाइल चलाने पर परिजनों की डांट से आहत छात्र ने की आत्महत्या

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी के बंथरा इलाके में मेमौरा छावनी रोड निवासी 16 वर्षीय जीत कुमार ने गुरुवार शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, बताया जाता है कि हाईस्कूल परीक्षा में कम अंक आने और ज्यादा मोबाइल चलाने पर पिता से मिली डांट से आहत होकर छात्र ने पंखे से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

मृतक छात्र की पहचान जीत कुमार (16) के रूप में हुई है, जीत मेमौरा छावनी रोड निवासी और वायुसेना से सेवानिवृत्त रंजीत कुमार का पुत्र था, जीत ने हाल ही में सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा दी थी, रिजल्ट में अंक उम्मीद से कम आने के कारण परिजन उसे भविष्य को लेकर समझा रहे थे और ज्यादा मोबाइल चलाने पर टोकते थे, गुरुवार शाम मोबाइल कम चलाने की हिदायत और डांट से नाराज होकर जीत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक गया.

परिजनों को शक तब हुआ जब कमरे के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई, आवाज सुनकर परिजन कमरे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. किसी तरह दरवाजा तोड़कर परिजन अंदर दाखिल हुए और जीत को फंदे से नीचे उतारा, उसे तुरंत मेमौरा छावनी स्थित एयरफोर्स के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पर पहुंची बंथरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, बंथरा थाना प्रभारी राना राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला कम नंबर आने और डांट से उपजे तनाव का लग रहा है, पुलिस मामले की हर पहलू की जांच कर रही है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

29 साल पहले हाथ गंवाने वाले को अब मिला 27 लाख का मुआवजा! रकम लेने के लिए ना पप्पू बचा, ना मां-बाप

1997 में बिजली विभाग की लापरवाही से सात साल के बच्चे पप्पू के दोनों हाथ काटने पड़े थे। अब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आगराः (जीएनएस)। कहते हैं कि अगर न्याय देर से मिले तो वह न मिलने के बराबर होता है। यूपी के आगरा के इस परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज से 29 साल पहले फरवरी 1997 में सात साल का बच्चा पप्पू अपने घर के बाहर खेल रहा था। अचानक वह गली में सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आ जाता है। करंट लगने से पप्पू बुरी तरह झुलस गया। गरीब घरवालों ने कर्जा लेकर किसी तरह उसका इलाज कराया पर उनके दोनों हाथ काटने पड़े। बिजली विभाग के लापरवाह कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुआवजे की आस में सोनू, फिर उसके उसके माता-पिता दुनिया छोड़ गए। सालों तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद अब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी राज्य विद्युत परिषद को पप्पू को 26.65 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सोनू के परिवार में अब केवल भाई प्रमोद और भाभी मिथिलेश हैं। प्रमोद बताते हैं कि पप्पू के साथ हुई इस दुर्घटना ने पूरे परिवार का सुख चैन छीन लिया। पप्पू के इलाज के लिए चार लाख रुपये का कर्जा लेना पड़ा। बिजली विभाग की तरफ से एक पैसे की मदद नहीं मिली। बेटे के साथ हुए हादसे के गम में पिता हरी सिंह की मौत हो गई। मां शांति देवी ने घरों में झाड़ू पोछा कर चार भाइयों का पालन पोषण किया। मई 2024 में पप्पू की मौत हो गई। उसके दुख में मां का भी निधन हो गया।

2005 में ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी

ये पूरा मामला नगलापदी इलाके का है। सात साल का पप्पू गली में खेल रहा था। वहीं सड़क पर बिजली विभाग ने खुले में 11 हजार वोल्ट का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। पप्पू इसकी चपेट में आ गया। बुरी तरह झुलसे बच्चे को घरवाले अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए पप्पू के दोनों हाथ काट दिए। पप्पू के पिता हरी सिंह ने मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई। टॉयल कोर्ट ने 2005 में यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि हादसा बच्चे की लापरवाही से हुआ। पिता ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब जाकर अदालत ने मुआवजा देने का आदेश दिया।

भाभी ने कहा- मुआवजे के लिए वकील की लेंगे मदद

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुआवजे के पैसे को बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी की जाए ताकि याची को हर महीने ब्याज मिलता रहे जिससे उसका जीवनयापन हो सके। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह याची को इस डिक्री का लाभ दिलाने में पूरी मदद करे। हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया पर इस मुआवजे का लाभ लेने के लिए पप्पू दुनिया में है ही नहीं। भाभी मिथिलेश का कहना है कि कई साल पहले पप्पू ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अब वह वकील की मदद से मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कराएंगी।

हेमा मालिनी ने भी राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति जताई।

'संसद का मजाक बना रखा है': कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को सुनना सिरदर्द था

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शुक्रवार को संसद में संबोधन के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने उनकी जमकर खिंचाई की है। कंगना रनौत ने कहा है कि वह पूरे देश और दुनिया में संसद का मजाक बना रहे हैं।

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने बचपन के सदमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें स्पीकर ने भी कहा कि रुक जाइए। उन्हें सुनना बहुत ही दुखदायी था।

'राहुल गांधी को सुनना सिरदर्द की तरह'

हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी के बारे में कहा, 'उन्हें सुनना सिरदर्द की तरह था। वे अपने बचपन के सदमें से गुजर रहे हैं। फिर उन्होंने मैजिक शो के बारे में बात की, जो उन्होंने बचपन में देखा था। एक मैजिशियन के टेबल पे...फिर उसे उन्होंने जंजीरों से बांधा था...उनको रात को कंपन होते

थे...और दादी कहानियां सुनाती थी। यह सब दुखदायी था।'

अध्यक्ष जी ने भी उन्हें (राहुल गांधी) कहा कि आप ये बंद करिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मजे आएंगे। आप मजे लो।

कंगना रनौत, बीजेपी सांसद

'राहुल गांधी ने संसद का मजाक बना दिया'

कंगना रनौत के अनुसार, 'हमें बहुत दुख है, सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है और उन्होंने संसद भवन का मजाक बना रखा है।'

हेमा मालिनी ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना

इसी तरह बीजेपी की एक और महिला सांसद हेमा मालिनी ने भी राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति जताई। हेमा मालिनी ने कहा, 'मैं यही कह सकती हूं कि यह एंटरटेनिंग था, लेकिन इसमें कुछ भी कंक्रीट नहीं था....प्रधानमंत्री को मैजिशियन कहना सही नहीं है। यह असंसदीय है।'

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर की टिप्पणी

इससे पहले राहुल गांधी ने अपने संबोधन में न सिर्फ अपने बचपन में जादू देखने का एक किस्सा सुनाया, बल्कि उससे जोड़कर पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसे सत्तापक्ष की आपत्ति के बाद सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया।

महिला आरक्षण बिल पर संबोधन के लिए आए थे राहुल

संसद में गुरुवार को मोदी सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए तीन बिल लेकर आई। उसी पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से इनके विरोध में अपना पक्ष रखने पहुंचे थे।

लखनऊ में शुरू हुआ 'दुग्ध स्वर्ण महोत्सव', पशुधन मंत्री धर्मपाल बोले- अब गाय कसाई को देखकर नहीं कांपती...

(जीएनएस)।

धर्मपाल सिंह ने कहा- वर्तमान में हमारे पास 7,500 गो संरक्षण केंद्र हैं, जहां लगभग 13.5 लाख गायों का पालन-पोषण किया जा रहा है. इन पर प्रतिदिन ₹8 करोड़ से अधिक का खर्च आता है. उन्होंने कहा कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती. मैं उद्यमियों और सक्षम नागरिकों से अपील करता हूं कि वे किसी भी एक गोशाला (200-300 गायों वाली) को एक वर्ष के लिए गोद लें.

लखनऊ के गोमती नगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दो दिवसीय 'दुग्ध स्वर्ण महोत्सव-2026' का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, दुग्ध विकास, पशुधन एवं राजनैतिक पेंशन धर्मपाल सिंह ने फीता काट कर दुग्ध महोत्सव का शुभारंभ किया. इस दौरान अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री सलाहगार,मुकेश कुमार मेश्राम अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास,धनलक्ष्मी के दुग्ध आयुक्त एवं महानिदेशक मत्स्य और निदेशक पशुपालन विभाग डॉ मेमपाल सिंह मौजूद रहे.

निराश्रित गोवंश सड़कों या खेतों में न दिखे

मीडिया से बातचीत में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कहा कि पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार में यही अंतर है कि पहले पशु चोरी के डर से किसान परेशान रहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून

का राज है. अब गाय कसाई को देखकर नहीं कांपती, बल्कि कसाई कानून को देखकर कांपता है. हमारा लक्ष्य है कि निराश्रित गोवंश सड़कों या खेतों में न दिखे, बल्कि उन्हें उचित संरक्षण और प्रेम मिले. आप सभी इस कार्य में सहयोग दें.

गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास

उन्होंने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है. मूत्र में गंगा मैया बसती हैं और इसका दूध अमृत के समान है. विशेष रूप से साहीवाल जैसी देसी नस्लों का दूध सर्वोत्तम माना जाता है. कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सपा के इशारे पर काम कर रहे हैं. गोमाता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सरकार के प्रयासों के बारे में मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गो संरक्षण के लिए दी जाने वाली दैनिक राशि को 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है.

गो संरक्षण पर प्रतिदिन 8 करोड़ रुपये का खर्च

धर्मपाल सिंह ने कहा- वर्तमान में हमारे पास 7,500 गो संरक्षण केंद्र हैं, जहां लगभग 13.5 लाख गायों का पालन-पोषण किया जा रहा है. इन पर प्रतिदिन 8 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आता है. उन्होंने कहा कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती. मैं उद्यमियों और सक्षम नागरिकों से अपील करता हूं कि वे किसी भी एक गोशाला (200-300 गायों वाली) को एक वर्ष के लिए गोद लें.

139 लाभार्थियों को भेजी गई नंद बाबा पुरस्कार की धनराशि

मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह, मंत्री, पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन, उ0प्र0 सरकार द्वारा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले पशुपालकों एवं उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया. साथ ही प्रदेश के समस्त जनपदों के विकासखण्ड स्तर पर चयनित 139 लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 के नंद बाबा पुरस्कार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी.

सफल किसान से विशेषज्ञ शामिल

महोत्सव में अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम और दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. समेत कई अधिकारी, किसान और विशेषज्ञ शामिल हुए. महोत्सव में दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी नई तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई है. प्रथम सत्र में गो पूजन, प्रदर्शनी का उद्घाटन, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार वितरण, प्रगतिशील गोपालकों, अग्रणी निवेशकों एवं प्रतिभाशाली नवाचारों का सम्मान किया गया.

लखनऊ से रफ्तार भरेगी टाटा की हाइड्रोजन बसें, ट्रकों का भी ट्रायल जारी

जमशेदपुर। (जीएनएस)। टाटा मोटर्स अब अपने लखनऊ प्लांट में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की मौजूदगी में 10 लाखवें वाहन के रोलआउट के दौरान यह अहम घोषणा की गई।

इसके साथ ही, टाटा ग्रुप ने अगले पांच साल में 20 लाख नए वाहन बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। भारत की दिग्गज कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अब प्रदूषण मुक्त परिवहन (क्लीन मोबिलिटी) की दिशा में एक नया अध्याय लिख रही है।

लखनऊ स्थित प्लांट ने हाल ही में 10 लाख कमर्शियल वाहन बनाने का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ है। इस उपलब्धि के जश्न में शामिल हुए एन. चंद्रशेखरन ने एलान किया कि कंपनी जल्द ही इस कारखाने में हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन इंटरनल

कंबशन इंजन (आईसीई) बसों का उत्पादन शुरू करेगी।

यह देश में लंबी दूरी के टिकाऊ सफर की ओर एक बड़ा और अहम कदम है। टाटा ग्रुप तेजी से अपने वाहनों की रेंज का विस्तार कर रहा है।

लग गए 34 साल

पारंपरिक डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाद अब कंपनी का मुख्य फोकस हाइड्रोजन तकनीक पर है। चंद्रशेखरन ने बताया कि प्लांट को 10 लाख का आंकड़ा छूने में 34 साल लगे, लेकिन भविष्य की योजनाएं कहीं अधिक तेज हैं।

अब कंपनी ने रफ्तार बढ़ाते हुए अगले सिर्फ पांच साल में 20 लाख और नए वाहन बनाने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है।

ट्रकों का चल रहा ट्रायल

इस बड़े मिशन में जमशेदपुर की भी बेहद खास भूमिका है। इन अत्याधुनिक हाइड्रोजन गाड़ियों का दिल यानी इनका इंजन जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस के कारखाने में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, शहर में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का ट्रायल भी लगातार चल रहा है।

भविष्य की जरूरतों को देखते हुए टाटा मोटर्स की यह दमदार पहल पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ भारतीय परिवहन व्यवस्था को एक नई ताकत देगी।

एनएचए द्वारा एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम के कार्यान्वयन की समीक्षा और उसमें तेजी लाने हेतु पुणे में दो-दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन

निवारक और प्रौद्योगिकी-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करना भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालियों को परिभाषित करेगा: श्रीमती मेघना सकोरे-बोर्डीकर, माननीय लोक स्वास्थ्य राज्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार

एनएचए ने कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने हेतु दिशानिर्देश, एनएचसीएक्स संबंधी रणनीति और एबीडीएम सूचकांक का अनावरण किया

नई पहलों का उद्देश्य भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार स्वास्थ्य सेवा कार्यबल का निर्माण करना और डिजिटल स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करना है

एनएचसीएक्स एकीकृत स्वास्थ्य संबंधी दावों के इकोसिस्टम के लिए एक परिवर्तनकारी सुधार के रूप में उभरा है

'सही' और 'बोध' को एबीडीएम के अगले चरण के प्रमुख सहायक कारकों के रूप में पहचाना गया है

(जीएनएस)।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पर दो-दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन पुणे में किया। इस शिविर में केन्द्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी इन प्रमुख स्वास्थ्य पहलों की प्रगति की व्यापक समीक्षा करने, उभरती प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने और इन पहलों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए।

उद्घाटन सत्र को महाराष्ट्र सरकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्रीमती मेघना सकोरे बोर्डीकर ने संबोधित किया। उन्होंने निवारक, समावेशी और प्रौद्योगिकी-आधारित

स्वास्थ्य सेवा की परिकल्पना पर जोर देते हुए प्रारंभिक जागरूकता और रोकथाम के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाराष्ट्र की बढ़ती पहलों और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका पर भी बल दिया। एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र कार्यान्वयन में नए मानदंड स्थापित करेगा।

इस चिंतन शिविर के पहले दिन, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने और भारत के डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और रणनीतिक पहलें हुईं। इनमें एबी पीएम-जेएवाई कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित एवं मानकीकृत करने हेतु दिशानिर्देशों का एक व्यापक संकलन जारी करना, एकीकृत एवं अंतरसंचालनीय स्वास्थ्य दावों के इकोसिस्टम को सक्षम बनाने हेतु एनएचसीएक्स रणनीति पत्र का अनावरण करना और राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों में एबीडीएम कार्यान्वयन के व्यवस्थित मूल्यांकन को सुगम बनाने हेतु एबीडीएम इंडेक्स संदर्भ मार्गदर्शिका जारी करना शामिल था। क्षमता के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कुशल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार स्वास्थ्य सेवा कार्यबल विकसित करने के एक राष्ट्रीय मंच के रूप में एनएचए डिजिटल हेल्थ अकादमी का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए चक्र (सेंटर फॉर हेल्थ एप्लाइड नॉलेज एंड रिसर्च ऑटोनोमी) और एनएचएसआरसी के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया।

चर्चा को दिशा देते हुए, एनएचए के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल ने स्वास्थ्य योजनाओं के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, वास्तविक समय में निगरानी को संभव बनाने में एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्मों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने, दावों का स्वतः निपटान, उन्नत डेटा विश्लेषण, एबीडीएम को तेजी से अपनाने और डिजिटल स्वास्थ्य अकादमी के जरिए निरंतर क्षमता के विकास सहित प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने एक आमूल बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए, मुख्य रूप से उपचारात्मक दृष्टिकोण से हटकर एक ऐसे निवारक और पूर्वानुमानित दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया जो विकसित भारत 2047 के तहत एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना के अनुरूप हो।

एबी पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन की व्यापक, डेटा-आधारित समीक्षा प्रस्तुत की गई। इसमें प्रमुख उपलब्धियों के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सत्र में आयुष्मान ऐप और व्हाट्सएप चैटबॉट का भी प्रदर्शन किया गया, जिनसे लाभार्थियों के लिए सेवाओं तक पहुंच और उपयोग में आसानी के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वतः निर्णय प्रक्रिया पर चर्चा के दौरान यह दिखाया गया कि एबी पीएम-जेएवाई के तहत दावों के त्वरित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निपटान को संभव बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा रहा है।